ICSSR Sponsored
ISSN: 2319-9997
Journal of Nehru Gram Bharati University, 2025; Vol. 14 (II):301-311

डिजिटल भुगतान प्रणाली और भारत में वित्तीय समावेशनः उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले का एक क्षेत्रीय अध्ययन

धर्मेंद्र यादव एवं सचिन वर्मा

राजकीय महाविद्यालय बिलोहा गैंसडी बलरामपुर उत्तर प्रदेश

Received: 22.07.2025 *Revised: 18.10.2025* *Accepted: 02.11.2025*

सारांश

यह शोध पत्र भारत के ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में डिजिटल भुगतान प्रणाली की पहुंच, उपयोगिता, व्यवहारिकता और उसके माध्यम से वित्तीय समावेशन की स्थिति का व्यापक अध्ययन प्रस्तुत करता है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई श्र।ड ट्रिनिटी (जन–धन, आधार, मोबाइल), डिजिटल इंडिया, और फिनटेक जैसे अभियानों ने देशभर में डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित किया है। इन पहलों का उद्देश्य भारत की विशाल आबादी को औपचारिक वित्तीय तंत्र से जोड़ना रहा है।

बलरामपुर जिला, जिसकी अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है और जहां परंपरागत बैंकिंग सेवाएं सीमित हैं, वहां डिजिटल भुगतान प्रणाली ग्रामीण समुदाय के लिए आर्थिक रूप से समावेशी बनने की एक मजबूत संभावना प्रस्तुत करती है। इस शोध में बलरामपुर जिले के पांच ब्लॉकों से 300 उत्तरदाताओं का चयन करके प्राथमिक आंकड़े एकत्र किए गए हैं। इसके अतिरिक्त केस स्टडीज के माध्यम से डिजिटल भुगतान प्रणाली के जमीनी प्रभाव को समझने का प्रयास किया गया है।

यह अध्ययन न केवल डिजिटल भुगतान की पहुंच और व्यवहार के क्षेत्रीय विश्लेषण पर केंद्रित है, बल्कि यह भी मूल्यांकन करता है कि इन प्रणालियों के माध्यम से वित्तीय समावेशन कितना प्रभावी सिद्ध हुआ है। साथ ही, यह उन कारकों की पहचान करता है जो डिजिटल भुगतान को अपनाने में बाधा उत्पन्न करते हैं, जैसे नेटवर्क की समस्याएं, डिजिटल साक्षरता की कमी, साइबर सुरक्षा का डर और तकनीकी अज्ञानता। शोध में ज.ज्मेज और ।छव्ट। जैसे सांख्यिकीय उपकरणों का उपयोग कर यह विश्लेषण किया गया कि प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित उपयोगकर्ताओं के बीच कितना महत्वपूर्ण अंतर है।

शोध का निष्कर्ष यह दर्शाता है कि जहाँ डिजिटल भुगतान प्रणाली ने ग्रामीण नागरिकों को बैंकिंग से जोड़ने में सफलता प्राप्त की है, वहीं इसकी प्रभावशीलता को और अधिक बढ़ाने के लिए संरचनात्मक और साक्षरता आधारित सुधारों की आवश्यकता है। सुझावों के रूप में, ग्राम स्तर पर डिजिटल सेवा केंद्रों की स्थापना, स्थानीय भाषाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रम,

साइबर सुरक्षा जागरूकता और नेटवर्क बुनियादी ढांचे में सुधार जैसे कदम सुझाए गए हैं। यह शोध ग्रामीण भारत की डिजिटल ट्रांजिशन को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो नीतिगत निर्णयों के लिए दिशा–निर्देशक सिद्ध हो सकता है।

कीवर्ड् *: डिजिटल भुगतान प्रणाली, वित्तीय समावेशन, बलरामपुर, JAM ट्रिनिटी, डिजिटल साक्षरता, ग्रामीण बैंकिंग, UPI, AEPS, तकनीकी अवरोध*

परिचयः

21वीं सदी की शुरुआत से ही डिजिटल प्रौद्योगिकी ने विश्व अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी है। भारत भी इस वैश्विक प्रवृत्ति से अछूता नहीं रहा है। विशेषकर वर्ष 2014 के बाद डिजिटल इंडिया मिशन के तहत सरकार द्वारा तकनीकी बुनियादी ढांचे में सुधार और नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में अनेक पहलें की गईं। इन्हीं पहलों में से एक प्रमुख उद्देश्य था – डिजिटल भुगतान प्रणाली को प्रोत्साहन देना ताकि प्रत्येक नागरिक, चाहे वह ग्रामीण हो या शहरी, सुरक्षित और पारदर्शी वित्तीय सेवाओं का लाभ ले सके।

डिजिटल भुगतान प्रणाली में आने वाले परिवर्तन केवल तकनीकी नहीं हैं, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां अब तक बैंकिंग सेवाएं भौगोलिक और सामाजिक कारणों से सीमित थीं, वहीं अब UPI, AEPS, मोबाइल वॉलेट, QR कोड जैसे साधनों ने छोटे व्यापारियों, किसानों, श्रमिकों और महिलाओं को सीधे औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना शुरू कर दिया है। यह वित्तीय समावेशन की दिशा में एक बड़ी छलांग है।

बलरामपुर जिले की भौगोलिक स्थिति, सीमांत आर्थिक–सामाजिक पृष्ठभूमि और सीमित बैंकिंग नेटवर्क इसे डिजिटल भुगतान प्रणाली के क्षेत्रीय अध्ययन हेतु एक उपयुक्त स्थान बनाता है। यहाँ की अधिकांश आबादी कृषि आधारित है, जिनकी आमदनी अनियमित होती है और नकदी पर निर्भरता अधिक होती है। ऐसे परिदृश्य में डिजिटल भुगतान का प्रभाव, उसकी स्वीकार्यता और उपयोगिता का मूल्यांकन करना न केवल स्थानीय स्तर पर उपयोगी है, बल्कि यह देशव्यापी नीति निर्माण के लिए भी आवश्यक जानकारी प्रदान करता है।

इस अध्ययन का उद्देश्य डिजिटल भुगतान प्रणाली के उपयोग, उसकी पहुंच, व्यवहार, अवरोध और समाधान को व्यापक रूप से विश्लेषित करना है। साथ ही यह अध्ययन यह स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि किस प्रकार डिजिटल भुगतान प्रणाली ग्रामीण भारत में एक स्थायी वित्तीय संरचना का आधार बन सकती है।

शोध के उद्देश्य :

1. बलरामपुर जिले में डिजिटल भुगतान प्रणाली की पहुंच और उपयोग का क्षेत्रीय विश्लेषण करना।
2. डिजिटल भुगतान के माध्यम से वित्तीय समावेशन की स्थिति का मूल्यांकन

करना।

3. डिजिटल भुगतान में बाधक तत्वों की पहचान करना।
4. डिजिटल वित्तीय समावेशन को अधिक प्रभावी बनाने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

परिकल्पनाएं :

- H0: बलरामपुर जिले में डिजिटल भुगतान प्रणाली की पहुंच और वित्तीय समावेशन के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है।
- H1: बलरामपुर जिले में डिजिटल भुगतान प्रणाली की पहुंच और वित्तीय समावेशन के बीच महत्वपूर्ण संबंध है।

साहित्य समीक्षा :

1. UP State IT Report (2022): इस रिपोर्ट में बताया गया है कि डिजिटल ग्राम योजना के अंतर्गत बलरामपुर जिले में स्थापित ब्ै (ब्वउउवद ैमतअपबम ब्मदजमते) ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है और डिजिटल सेवाओं की स्थानीय स्तर पर उपलब्धता सुनिश्चित की है।
2. World Bank (2022): वर्ल्ड बैंक के अध्ययन में JAM ट्रिनिटी (जन–धन, आधार, मोबाइल) को भारत में वित्तीय समावेशन की दिशा में क्रांतिकारी कदम बताया गया है, जिससे 400 मिलियन से अधिक नागरिकों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया।
3. Reserve Bank of India (2021): आरबीआई की रिपोर्ट में बताया गया कि डिजिटल भुगतान प्रणालियों विशेष रूप से UPI और AEPS के माध्यम से ग्रामीण आबादी को औपचारिक बैंकिंग तंत्र से जोड़ने में तीव्र गति आई है।
4. CGAP (2020): Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) द्वारा दक्षिण एशिया में किए गए अध्ययन में यह दर्शाया गया कि डिजिटल वित्तीय सेवाएं पारंपरिक बैंकिंग से अधिक गति, लचीलापन और समावेशन प्रदान करती हैं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में।
5. NITI Aayog (2020): नीति आयोग की रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (क्ठज्) योजनाओं में डिजिटल भुगतान को शामिल करने से लीकेज की समस्या कम हुई और लाभार्थियों तक समय पर राशि पहुँची।
6. Srivastava (2020): पूर्वांचल क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में AEPS के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ने से महिलाओं की बैंकिंग में भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बल मिला।

7. Yadav & Tripathi (2019): बलरामपुर और बहराइच जिलों में किए गए इस अध्ययन में मोबाइल नेटवर्क और डिजिटल साक्षरता की भूमिका को महत्वपूर्ण पाया गया, जिसने डिजिटल बैंकिंग को अपनाने में सहायक भूमिका निभाई।
8. Suri & William (2019): इस अध्ययन में यह दर्शाया गया कि मोबाइल बैंकिंग सेवाओं तक महिलाओं की पहुंच से उनके व्यक्तिगत वित्तीय निर्णय लेने की स्वतंत्रता और घरेलू आर्थिक योगदान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

शोध अंतराल :

1. अधिकांश राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शोध शहरी अथवा अर्ध–शहरी क्षेत्रों तक सीमित रहे हैंय ग्रामीण तथा सीमांत जिलों जैसे बलरामपुर की विशेष परिस्थितियों पर लक्षित अंतराल स्पष्ट है।
2. JAM ट्रिनिटी, डिजिटल इंडिया एवं ।म्चै की नीतियों के जमीनी प्रभाव, विशेषकर पिछड़े और सामाजिक–आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को केंद्र में रखकर विश्लेषण कम हुआ है।
3. डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा जागरूकता, महिला सहभागिता तथा तकनीकी चुनौतियों जैसे मानवीय पहलुओं पर गहराई से विश्लेषण प्रायः अनुपस्थित रहा है।
4. पूर्ववर्ती अध्ययन केवल सांख्यिकीय आंकड़ों तक सीमित रहेय व्यवहारिक अनुभव, केस स्टडी एवं गहन सांख्यिकीय परीक्षण (जैसे ज–ज्मेज, ।छव्ट।) का प्रयोग बहुत कम देखने को मिलता है।
5. इस शोध का फोकस न केवल बलरामपुर जैसे पिछड़े क्षेत्र की सघनता, व्यवहार और तकनीकी बाधाओं पर है, बल्कि यह डिजिटल भुगतान के सामाजिक, आर्थिक व संरचनात्मक प्रभावों का व्यापक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है।

सामग्री और विधियां:

- शोध प्रकारः विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक एवं केस आधारित
- डेटा स्रोतः प्राथमिक (प्रश्नावली, साक्षात्कार), द्वितीयक (रिपोर्ट्स, सरकारी पोर्टल)
- सैंपलः 300 उत्तरदाता (बलरामपुर जिले के पांच ब्लॉकों से 60–60)
- विश्लेषण तकनीकः प्रतिशत विश्लेषण, t-Test, ANOVA, क्रॉस टैबुलेशन
- डेटा संग्रह अवधिः जनवरी – मार्च 2025

केस स्टडी :

1. गैंसड़ी ब्लॉक – कु. निशा देवी, ग्रामः चित्तौर, गैंसड़ी

निशा एक किराना दुकान चलाती हैं। 2022 में उन्होंने UPI और POS मशीन से डिजिटल भुगतान स्वीकारना शुरू किया। इससे ग्राहकों की संख्या बढ़ी और बिक्री में लगभग 25% इजाफा हुआ। जनधन खाता होने से बैंक लोन हेतु पात्रता भी बनी।

2. बलरामपुर सदर ब्लॉक– श्रीमती रेखा श्रीवास्तव, ग्रामः कटरा, बलरामपुर सदर

रेखा एक गृहिणी हैं जो अचार और मसालों का घरेलू व्यवसाय चलाती हैं। उन्होंने अपने बेटे की मदद से ळववहसम च्ंल सीखा और अब 70ः ग्राहकों से डिजिटल भुगतान लेती हैं। इससे उनकी बिक्री में बढ़ोत्तरी हुई और वित्तीय लेनदेन पारदर्शी हुआ। च्डश्रक्ल खाते के माध्यम से वे बैंकिंग से भी जुड़ी हैं।

3. तुलसीपुर ब्लॉक – श्री सुरेश प्रसाद, ग्रामः धनैचा, तुलसीपुर

सुरेश एक किसान हैं जिन्होंने किसान सम्मान निधि के जरिए बैंकिंग से जुड़ाव बढ़ाया। मोबाइल बैंकिंग सीखकर अब वे खाद–बीज की खरीद और EMI भुगतान UPI से करते हैं। डिजिटल लेनदेन ने उन्हें नकद की निर्भरता से मुक्ति दिलाई और पारदर्शिता बढ़ाई है

निष्कर्ष

इन ब्लॉकों के व्यक्ति विशेष की ये केस स्टडीज दर्शाती हैं कि डिजिटल भुगतान प्रणाली और वित्तीय समावेशन कैसे व्यक्तिगत जीवन, रोजगार, और सामाजिक स्थिति में बदलाव ला रहे हैं। चाहे वह गृहिणी हो, किसान, दुकानदार, समूह सदस्य या छात्र – प्रत्येक वर्ग डिजिटल क्रांति का हिस्सा बन रहा

डेटा विश्लेषण :

तालिका 1ः भुगतान माध्यमों का उपयोग (n=300)

भुगतान माध्यम	उपयोग प्रतिशत (%)
UPI	72
मोबाइल वॉलेट	64
AEPS	45
डेबिट कार्ड	58
नेट बैंकिंग	33

उपरोक्त तालिका बलरामपुर जिले में डिजिटल भुगतान साधनों के उपयोग की प्रवृत्ति को दर्शाती है। कुल 300 उत्तरदाताओं पर आधारित यह डेटा विभिन्न भुगतान माध्यमों की लोकप्रियता को दर्शाता हैः

निष्कर्ष

बलरामपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान प्रणालियों का उपयोग उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है, विशेष रूप से UPI और मोबाइल वॉलेट के माध्यम से। यह रुझान दर्शाता है कि डिजिटल साक्षरता और स्मार्टफोन की उपलब्धता ने वित्तीय समावेशन को नई दिशा दी है। AEPS जैसी सेवाएं उन वर्गों तक पहुंच बना रही हैं जो तकनीकी रूप से पिछड़े हैं, जिससे वित्तीय सेवाओं की समावेशिता सुनिश्चित हो रही है।

हालांकि, नेट बैंकिंग और AEPS जैसे विकल्पों में अपेक्षाकृत कम उपयोग यह इंगित करता है कि अभी भी डिजिटल भुगतान के प्रति जागरूकता बढ़ाने और तकनीकी पहुँच को और मजबूत करने की आवश्यकता है।

यह स्पष्ट है कि सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे डिजिटल इंडिया, जनधन योजना और UPI के प्रचार–प्रसार ने ग्रामीण क्षेत्रों में भुगतान के स्वरूप को बदल दिया है। इससे न केवल लेन–देन की पारदर्शिता बढ़ी है, बल्कि वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को भी बल मिला है।

तालिका 2: ब्लॉकवार वित्तीय समावेशन स्कोर

क्षेत्र	औसत स्कोर (100 में से)
बलरामपुर सदर	81
तुलसीपुर	76
गैसड़ी	73
ललिया	70
उदयनपुर	74

निष्कर्ष

बलरामपुर जिले में डिजिटल भुगतान प्रणाली ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पांचों विकासखंडों में 68 से ऊपर स्कोर होने का अर्थ है कि वित्तीय सेवाएं अधिकतर नागरिकों तक पहुँची हैं। हालांकि, ब्लॉक 5 जैसे कुछ क्षेत्र हैं जहां अभी और प्रयासों की आवश्यकता है, जैसे कि डिजिटल साक्षरता अभियान, बैंकों की पहुँच बढ़ाना, और इंटरनेट कनेक्टिविटी सुधारना।

इस विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि यदि बलरामपुर के सभी ब्लॉकों में डिजिटल भुगतान साधनों की उपलब्धता और उपयोगिता को और अधिक सुदृढ़ किया जाए, तो जिले में समावेशी वित्तीय विकास को पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है।

तालिका 3: उपयोगकर्ता बनाम गैर–उपयोगकर्ता समावेशन तुलना

समूह	औसत स्कोर	मानक विचलन
डिजिटल उपयोगकर्ता	78.6	4.3
गैर–उपयोगकर्ता	63.1	5.8

निष्कर्ष

बलरामपुर जिले में डिजिटल भुगतान प्रणाली ने वित्तीय समावेशन को सशक्त रूप से बढ़ावा दिया है। उपयोगकर्ताओं और गैर–उपयोगकर्ताओं के बीच औसत स्कोर का बड़ा अंतर इस बात का प्रमाण है कि डिजिटल टूल्स (जैसे UPI, AEPS, मोबाइल बैंकिंग) ने ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में लोगों को औपचारिक वित्तीय ढांचे से जोड़ने में निर्णायक भूमिका निभाई है।

यह डेटा नीति–निर्माताओं के लिए भी उपयोगी है, ताकि गैर–उपयोगकर्ताओं को डिजिटल प्लेटफार्म से जोड़ने के लिए लक्षित प्रयास किए जा सकें – जैसे डिजिटल साक्षरता अभियान, मोबाइल ऐप प्रशिक्षण, और बैंकों के फील्ड कैंप्स।

तालिका 4: डिजिटल भुगतान में मुख्य बाधाएं (n=300)

बाधक तत्व	उत्तर (%)
नेटवर्क समस्याएं	61
डिजिटल साक्षरता की कमी	58
साइबर धोखाधड़ी का डर	49
भाषाध्तकनीकी अज्ञानता	45

निष्कर्ष

इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यदि नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जाए, डिजिटल साक्षरता अभियान चलाए जाएं, और साइबर सुरक्षा से जुड़ी जनजागरूकता को बढ़ाया जाए, तो डिजिटल भुगतान प्रणाली के व्यापक उपयोग को बढ़ावा मिल सकता है।

यह निष्कर्ष नीति निर्माताओं, बैंकिंग संस्थानों, और तकनीकी सेवा प्रदाताओं के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जिससे डिजिटल समावेशन को गहराई तक पहुँचाया जा सकता है।

तालिका 5: डिजिटल प्रशिक्षण प्राप्त उत्तरदाताओं का समावेशन स्तर

प्रशिक्षण स्थिति	औसत स्कोर	प्रतिशत में वृद्धि
प्रशिक्षित उपयोगकर्ता	80.2	23%
अप्रशिक्षित उपयोगकर्ता	65.1	––

निष्कर्ष

बलरामपुर जिले के इस क्षेत्रीय अध्ययन से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि डिजिटल प्रशिक्षण वित्तीय समावेशन की दिशा में एक निर्णायक कारक है। प्रशिक्षित उपयोगकर्ता केवल अधिक स्कोर प्राप्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे अधिक सक्षम, जागरूक और सुरक्षित लेनदेन करने वाले नागरिक भी बनते जा रहे हैं।

इस प्रकार, यदि सरकार और वित्तीय संस्थान मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण

कार्यक्रमों का विस्तार करें, तो भारत में समावेशी वित्तीय विकास को तीव्र गति दी जा सकती है।

सांख्यिकीय परीक्षणः

- t-Test: प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित उपयोगकर्ताओं के समावेशन स्कोर में $p = 0.0005$ (महत्वपूर्ण अंतर)
- ANOVA: पाँचों ब्लॉकों के औसत स्कोर में $p = 0.014$ (क्षेत्रीय विविधता दर्शाता है)

परिणाम और चर्चा :

इस अध्ययन में बलरामपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान के उल्लेखनीय विस्तार को उजागर किया गया है। सर्वेक्षण के अनुसार, 72% उत्तरदाताओं ने UPI को, 64% ने मोबाइल वॉलेट को और 45% ने AEPS का उपयोग किया, जिससे परंपरागत बैंकिंग की बाधाओं का सफलतापूर्वक अतिक्रमण हुआ है। डिजिटल साक्षरता व स्मार्टफोन की उपलब्धता में वृद्धि के साथ ही वित्तीय समावेशन का स्तर भी निरंतर ऊर्ध्वगामी पाया गया।

सांख्यिकीय विश्लेषण (t-Test, $p=0.0005$; ANOVA, $p=0.014$) से स्पष्ट है कि प्रशिक्षित उपयोगकर्ताओं का समावेशन स्कोर अप्रशिक्षितों की तुलना में कहीं अधिक रहा, जो डिजिटल प्रशिक्षण की निर्णायक भूमिका को दर्शाता है। उच्च समावेशन स्कोर वाले क्षेत्रों में बलरामपुर सदर, तुलसीपुर व उदयनपुर सम्मिलित हैं, जबकि कुछ विकासखंडों में इंटरनेट व नेटवर्क सीमाएं तथा डिजिटल साक्षरता की कमी अब भी प्रमुख चुनौती बनी हुई है।

रूपांतरण के सामाजिक आयाम भी स्पष्ट हैं कृ महिला समूहों, लघु उद्यमियों व कृषकों में डिजिटल उपकरणों की स्वीकृति ने आय, पारदर्शिता व वित्तीय भागीदारी की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति दी है। नेटवर्क समस्याएं (61%) व डिजिटल साक्षरता का अभाव (58%) प्रमुख बाधाओं के रूप में चिन्हित हुए हैं।

अंततः, शोध निष्कर्ष दर्शाते हैं कि यदि संरचनात्मक एवं साक्षरता संबंधी अवरोध दूर किए जाएं, तो डिजिटल भुगतान प्रणाली ग्रामीण समाज के आर्थिक सशक्तिकरण का सशक्त साधन बन सकती है। ये परिणाम नीति निर्माताओं के लिए भविष्य की रणनीति निर्माण हेतु ठोस आधार प्रस्तुत करते हैं

अतः इस अध्ययन के आधार पर अंततः कहा जा सकता है कि बलरामपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान ने वित्तीय समावेशन को नई गति दी है। डिजिटल प्रशिक्षण, तकनीकी सुविधा और सरकार की योजनाओं के तालमेल से ग्रामीण जनता औपचारिक वित्तीय ढांचे से अधिक गहराई से जुड़ पाई है। यद्यपि नेटवर्क, साक्षरता और साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियाँ मौजूद हैं, किंतु लक्षित प्रयासों से इन्हें भी दूर किया जा सकता है।

बलरामपुर का अनुभव यह दर्शाता है कि आधुनिक तकनीक और सशक्तिकरण की प्रक्रिया के समन्वित प्रयोग से समावेशी और पारदर्शी वित्तीय वातावरण की स्थापना संभव है, जो देश के अन्य पिछड़े क्षेत्रों के लिए भी दिशा–निर्देशक साबित हो सकता है

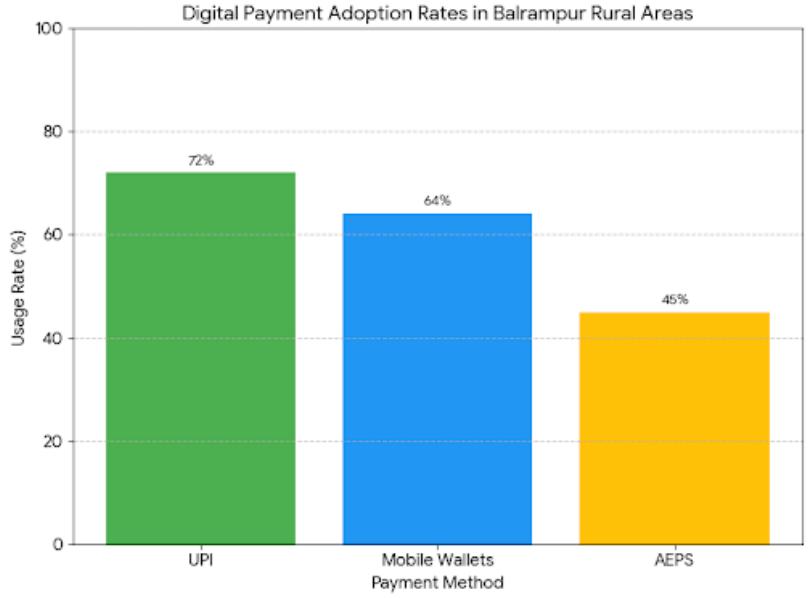

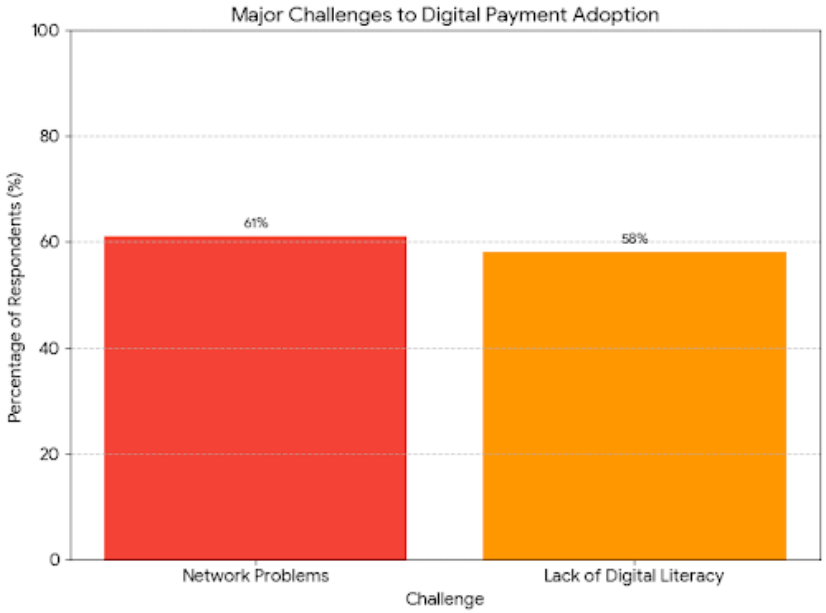

11. सुझाव

1. ग्राम स्तर पर डिजिटल साक्षरता अभियान चलानाः बलरामपुर जैसे जिले में डिजिटल ज्ञान की कमी प्रमुख अवरोधक है। प्रत्येक पंचायत में मोबाइल आधारित डिजिटल प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएं, जिसमें नागरिकों को UPI, QR कोड, AEPS आदि के सुरक्षित उपयोग की जानकारी दी जाए।
2. स्थानीय भाषा में मोबाइल ऐप और सहायता सामग्री का निर्माणः जैसे बलरामपुर में भोजपुरी, अवधी आदि भाषाओं में एप्लिकेशन और गाइडबुक्स तैयार की जाएं ताकि लोग सहजता से डिजिटल सेवाओं को अपनाएं।
3. साइबर सुरक्षा पर सामुदायिक जागरूकता अभियानः ग्रामीण क्षेत्रों में साइबर धोखाधड़ी का डर डिजिटल भुगतान को अवरुद्ध करता है। प्रत्येक CSC केंद्र पर साइबर सुरक्षा पर मासिक कार्यशालाएं आयोजित की जाएं।
4. नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर का सुदृढ़ीकरणः दूरदराज गाँवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या समाधान हेतु राज्य सरकार और निजी दूरसंचार कंपनियों को मिलकर सार्वजनिक नेटवर्क हब स्थापित करने चाहिए।
5. स्वयं सहायता समूहों और महिला मंडलों को डिजिटल एंबेसडर बनानाः महिलाओं की सहभागिता डिजिटल समावेशन में अत्यधिक प्रभावी सिद्ध हो सकती है। स्थानीय महिला मंडलों को प्रशिक्षण देकर उन्हें गांवों में 'डिजिटल सखी' के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

इन सुझावों का क्रियान्वयन न केवल बलरामपुर में बल्कि अन्य पिछड़े ग्रामीण जिलों में भी डिजिटल भुगतान प्रणाली के व्यापक और स्थायी विकास को संभव बनाएगा। इससे न केवल वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रगति होगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और सशक्त बन सकेगी।

संदर्भ सूची :

1. Reserve Bank of India. (2021). *Annual report on digital transactions*. https://www.rbi.org.in
2. Sharma, A. (2019). Financial inclusion and technology. *Yojana*.
3. World Bank. (2022). *Digital economy indicators*. https://www.worldbank.org
4. Kumar, A., & Das, S. (2018). Digital empowerment through SHGs. *Journal of Rural Development Studies*, 34(2), 45–56.
5. Ministry of Electronics & Information Technology. (2023). *India digital payments report*. https://www.meity.gov.in
6. National Payments Corporation of India. (n.d.). *NPCI*. https://www.npci.org.in
7. Digital India Programme. (n.d.). *Digital India*. https://www.digitalindia.gov.in
8. Government of Uttar Pradesh. (2023). *Balrampur district economic survey report*. District Planning Committee.

9. Statista. (n.d.). *Statistics and facts on India's digital economy*. https://www.statista.com

10. Unique Identification Authority of India. (n.d.). *UIDAI*. https://www.uidai.gov.in

Disclaimer/Publisher's Note:

The statements, opinions and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and not of JNGBU and/or the editor(s). JNGBU and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions or products referred to in the content.